श्री सुरजीत सिंह बरनाला : आंकड़े तो मिल नहीं सकते हैं ।

श्री राज केशर सिंह : क्या सरकार उन किसानों को वैज्ञानिक तरीके अपनाने के लिए किसी प्रकार की सब्सिडी भी देती है ? यदि हां, तो किस मात्रा में और यदि नहीं तो क्या सरकार भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की सब्सीडी देने पर विचार कर रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सब्सिडी का जहां तक ताल्लुक है--इसमें साइन्टिफिक मैथड्स यूज करने के लिये कोई पैसा नहीं दिया जाता है । इसके नीचे बहुत सी स्कीमें हैं--दिस इज ए पैकेज आफ प्रैक्टिसिज--जिसमें उनको सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन पैसा नहीं दिया जाता है ।

SHRI HITENDRA DESAI: Is the Government satisfied with all the various schemes mentioned in the statement? Has the Government in mind any other scheme for development of agriculture? What is the target of agricultural production this year?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The target of agricultural poduction this year is 118 million tonnes. So far as the working of the schemes is concerned, we are quite satisfied with the working of the various schemes but we are making more and more efforts that the working should improve further. For the time being we do not have any new scheme to add to the present one.

श्री लालजी भाई : सरकार ने छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिये अनेकों योजनाएं बनाई हैं, जिनमें एक यह भी है कि 10 बीघे वाले किसानों से लगान न लिया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि यह लगान कब से माफ किया जायेगा । केन्द्र सरकार इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कब तक आदेश देगी और किस तारीख से उनका लगान माफ हो जायगा ?

इस योजना के अन्तर्गत छोटे किसानों को जो अन्य सुविधाएं दी जानी हैं जैसे लेवी न ली जाय, इन सुविधाओं के बारे में भी कुछ डिटेल में बतलायें, वे कौन-कौन सी सुविधाएं हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : लगान का जहां तक ताल्लुक—अलग-अलग राज्य अपने हिसाब से इस काम को कर रहे हैं । किसी ने माफ कर दिया है, किसी ने ज्यादा कर दिया है और किसी ने कम कर दिया है । इस काम में हम गाइड नहीं कर सकते हैं, वे अपने-अपने राज्य के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस काम को कर रहे हैं ।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: The hon'ble Minister says that they are implementing the scientific schemes. Sir, without giving assistance to the small farmers how can they implement the schemes?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Assistance in many forms is being given. As I have already said, it is a package of practices and it is all assisted by the Government in this matter.

Drought Prone Area Programme during Sixth Plan

*273. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Drought Prone Area Programme is to be continued in the Sixth Five Year Plan also;

(b) whether the amount to be spent is likely to be enhanced during Sixth Five Year Plan; and

(c) whether money is to be spent on developing and exploiting ground water resources in the country during that period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yes, subject to modifications considered necessary in the programme itself and the changes that may be brought about by the new approach to Integrated Rural Development.

(b) Yes.

(c) Yes, Sir, in view of the increased emphasis on ground water development.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I would like to know why is it that in the drought prone areas where Drought Prone Area Programme is existing, the small farmers' development agencies programme has not been implemented?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, these are the proposals which are under consideration. That is why I have said: We propose to bring about certain changes that may be considered necessary in the new approach to Integrated Rural Development.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Drought prone area programme is an area programme whereas small farmers development agency programme is meant to give individual assistance to the farmers. Therefore in the Area programme potentiality will be created. Unless small farmers and agriculturists are assisted how can they exploit the potentialities created?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: The new approach will include new rural industries, self employment programmes. That main elements of DPRP and SFDP will be brought to bear on such areas covered by any of those programmes depending upon the suitability of the programme. That is also under consideration.

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष भयंकर सूखा पड़ता है और इससे किसानों की बहुत क्षति हुआ करती है, तो क्या कृषि मंत्री जी सिंचाई के लिए कोई विशेष प्राथमिकता देने की योजना बना रहे हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : सिंचाई पर सबसे अधिक ध्यान यह वर्तमान सरकार देने के लिए वचनबद्ध है । मैं सूचना के लिए यह बताना चाहता हूं कि 1950–51 में 23 मिलियन हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी और पिछले वर्ष 46 मिलियन हेक्टेयर भूमि की व्यवस्था हुई है । इस प्रकार से 25 वर्ष में सिर्फ 23 मिलियन हेक्टेयर भूमि में सिंचाई में वृद्धि हुई है जबकि वर्तमान सरकार ने अगले 5 वर्ष में 17 मिलियन हेक्टेयर भूमि में और सिंचाई करने का प्रोग्राम बनाया है ।

डा० रामजी सिंह : क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में सूखाग्रस्त क्षेत्र जिसको आप मानते हैं, वह कितना है और जैसा आपने कहा कि अण्डरग्राउण्ड वाटर रिसोर्सेज को आप टैप करने जा रहे हैं, तो क्या आपको यह मालूम है कि जहां इसके लिए रीबोरिंग की जरूरत है, वह उस को किया जाए । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जियोलोजीकल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट है कि बिहार में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर रीबोरिंग हो सकती है और अण्डरग्राउण्ड वाटर को टैप किया जा सकता है । क्या आप जियोलाजीकल सर्वे आफ इण्डिया को यह निर्देश देंगे कि वह फिर

से उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करे और अगर इन क्षेत्रों में नीचे पहाड़ और पत्थर हैं, तो क्या वहां पर आप पर्याप्त रीबोरिंग की व्यवस्था करेंगे ?

श्री भानुप्रताप सिंह : हमारा उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करें परन्तु साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने में कितना व्यय आता है । जहां पर बहुत ज्यादा पत्थर और चट्टानें हैं, उनको तोड़ कर बहुत नीचे से पानी निकालने में बहुत ज्यादा खर्च होता है । अभी इस प्रकार की टेस्ट बोरिंग वगैरह हुई है और उसकी इकोनामी को ध्यान में रखते हुए हम जरूर अधिक से अधिक सिंचाई की व्यवस्था करने की व्यवस्था करेंगे ।

SHRI NANJESHA GOWDA: There are various schemes for employment, whether DAP or SFDP. All these years we have been giving the schemes to the state governments or some officers but we have seen how those schemes have failed. Would the Minister assure us that responsibility would be fixed on a particular officer in consultation with the state government to implement those schemes and within a particular time so that we can see some progress? Would the hon. Minister give us that assurance?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: There may be some confusion here and there about the rural development programme but I want to submit that it is as a result of such programmes that the country is self-sufficient in foodgrains.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: My point is that the Drought Prone Area Programmes are normally introduced with a view to provide employment and some other development works. But, if at all, we have to make an impact on the drought prone areas, the main question and the main responsibility will be to introduce the dry farming techniques. I would like to know whether we have made any organised efforts in this matter, whether new approach is being thought of, whether the new scientific researches that are being undertaken are being introduced here and whether we want to make the introduction of dry farming techniques a part of the Drought Prone Area Programme.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Yes, Sir. That is very much so. In fact, I had stated earlier that the main elements of DPAP, SFAD and CAD Programmes will be brought to bear on each other. Now it will not be any more an isolated programme. We want to integrate them to get better results.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पीछे जब ड्राट प्रोन एरियाज का सर्वे हुआ था तो पिछली सरकार ने जिन कई जिलों को राजनीतिक कारणों से ड्राट प्रोन एरियाज की सूची में सम्मिलित करने से छोड़ दिया था और जिनमें अधिकतर सूखा पड़ा करता है तो क्या मंत्री जी ऐसा प्रयास करेंगे कि ऐसे जिलों को भी सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाए ताकि उन जिलों को भी सिंचाई आदि की सभी सुविधाएं मिल सकें जो ऐसे क्षेत्रों को मिला करती हैं ? क्या आप ऐसा प्रयास करेंगे कि जो क्षेत्र पीछे इस सूची में आने से रुक गये थे, उन्हें भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए ?

श्री भानुप्रताप सिंह : अगर माननीय सदस्य, किसी ऐसे जिले की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे तो हम जरूर विचार करेंगे ।